

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.12.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 256 का उत्तर

कर्नाटक के हासन जिले में रेलवे उपरि पुल (आरओबी) और पैदल उपरि पुल (एफओबी)

\*256. श्री श्रेयस एम. पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कर्नाटक के हासन जिले में वर्तमान में स्टेशन-वार कितने सड़क उपरि पुल (आरओबी) और पैदल उपरि पुल (एफओबी) मौजूद हैं;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जिले के लिए स्वीकृत आरओबी और एफओबी का उनकी स्वीकृत लागत, वर्तमान स्थिति और पूरा करने की समय-सीमा सहित ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को हासन जिले में आरओबी/एफओबी के निर्माण/उन्नयन के लिए कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान जिले में आरओबी/एफओबी कार्यों के लिए आवंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अतिरिक्त आरओबी/एफओबी अवसंरचना के माध्यम से यात्री और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 17.12.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 256 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड): भारतीय रेल में उपरि/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति और निष्पादन सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव के आधार पर इनकी प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (अक्टूबर 2025) के दौरान भारतीय रेल में निर्मित उपरि/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित आरओबी/आरयूबी
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (अक्टूबर 2025)	13,653 अदद

01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,11,583 करोड़ रु. की लागत पर 4689 अदद उपरि/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें कर्नाटक राज्य में 3,920 करोड़ रु. की लागत पर 127 अदद उपरि/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो नियोजन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

वर्ष 2014 से हसन जिले में 09 आरओबी एवं 04 एफओबी निर्मित किए गए हैं। हसन जिले में आरओबी एवं एफओबी के वर्तमान कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	आरओबी/ एफओबी	लागत (करोड़ रु. में)	टिप्पणियां
1.	हसन-सकलेशपुर खंड पर समपार सं.3 (हसन के निकट)	आरओबी	101.790	2 लेन वाला आरओबी नवंबर 2023 में कमीशन कर दिया गया है। शेष 2 लेन (सीमित ऊंचाई वाले भूमिगत कैरिजवे) का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

2.	मैसूर-अरसीकेरे खंड पर कोरावांगला-बागेशपुरा स्टेशनों के बीच कि.मी. 133/300-400 के बीच समपार सं. 112	आरओबी	24.079	विशेष रेल परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
3.	मैसूर-हसन खंड के होल नरसीपुर-माविनकेरे स्टेशनों के बीच कि.मी. 87/800-900 पर समपार सं. 78	आरओबी	32.400	रेलवे के हिस्से में सुपरस्ट्रक्चर का फेब्रिकेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। पहुँच मार्ग में फाउंडेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, भूमि अधिग्रहण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
4.	हसन-अरसीकेरे खंड पर समपार सं. 131	आरओबी	44.867	विशेष रेल परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
5	मैसूर-अरसीकेरे खंड पर कि.मी. 74/000-100 पर समपार सं. 68	आरओबी	15.935	विशेष रेल परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
6.	हसन-अरसीकेरे खंड पर कि.मी. 104/100 पर अनधिकृत क्रॉसिंग समाप्त करने हेतु 3 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पुल	एफओबी	1.712	उपसंरचना का कार्य पूरा कर दिया गया है। गर्डर फेब्रिकेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है।
7.	अमृत भारत योजना के अंतर्गत हसन पर 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का प्रावधान	एफओबी	6.960	फाउंडेशन कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

8.	अमृत भारत योजना के अंतर्गत अरसीकेरे पर 12 मीटर चौड़े उपरी पैदल पुल का प्रावधान	एफओबी	6.890	फाउंडेशन कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
----	--	-------	-------	------------------------------------

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	835 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	7,564 करोड़ रु. (9 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 3,264 किलोमीटर लंबाई की 25 परियोजनाएं (15 नई लाइनें, 10 दोहरीकरण) जिनकी लागत 42,517 करोड़ रु. है, स्वीकृत की गई हैं। इनका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रु में)
नई लाइन	15	2,034	421	8,794
दोहरीकरण/ बहुपथन	10	1,230	973	12,516
कुल	25	3,264	1,394	21,310

कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	कोत्तूर-हरिहर नई लाइन (65 किलोमीटर)	468
2	हासन-बेंगलोर नई लाइन (167 किलोमीटर)	1,290
3	बीदर-गुलबर्गा नई लाइन (110 किलोमीटर)	1,543

4	शिवानी-होसदुर्ग सड़क दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	50
5	शिवानी-बिरुर दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	143
6	होसदुर्ग-चिकजाजुर दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	260
7	रामनगरम-मैसूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (94 किलोमीटर)	998
8	यलहंका-चन्नसंद्रा दोहरीकरण (13 किलोमीटर)	108
9	यशवंतपुर-यलहंका दोहरीकरण (12 किलोमीटर)	95
10	नेत्रावती-मंगलौर सेंट्रल दोहरीकरण (2 किलोमीटर)	28
11	कनकनाडि-पनम्बूर दोहरीकरण (19 किलोमीटर)	350
12	अरसीकेरे-तुमकूर दोहरीकरण (96 किलोमीटर)	758
13	यलहंका-पेनुकोंडा दोहरीकरण (123 किलोमीटर)	1,104
14	दौंड-गुलबर्गा दोहरीकरण (225 किलोमीटर)	3,182
15	हुबली-चिकजाजुर दोहरीकरण (190 किलोमीटर)	1,850

कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जो शुरू की गई हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1.	होसपेट-हुबली-लॉंडा-वास्को-द-गामा दोहरीकरण (312 किलोमीटर)	4,153
2.	होटगी-गदग दोहरीकरण (284 किलोमीटर)	2,459
3.	गिणिगेरा - रायचूर नई लाइन (165 किलोमीटर)	3,401
4.	गदग - वाडी नई लाइन (257 किलोमीटर)	2,842
5.	बागलकोट - कुडची नई लाइन (142 किलोमीटर)	1,649
6.	तुमकूर - रायदुर्ग नई लाइन (207 किलोमीटर)	2,496
7.	तुमकूर - दावणगेरे नई लाइन (182 किलोमीटर)	2,142
8.	कडूर - चिकमगलूर-बेलूर नई लाइन (68 किलोमीटर)	825
9.	बैयप्पनहल्ली - होसुर दोहरीकरण (48 किलोमीटर)	336
10.	यशवंतपुर - चन्नसंद्रा दोहरीकरण (22 किलोमीटर)	314
11.	बल्लारी -चिकजाजूर दोहरीकरण (185 किलोमीटर)	3,079

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 7,239 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाले 65 सर्वेक्षण कार्य (25 नई लाइन और 40 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण के कारण लंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	परियोजना	अपेक्षित कुल भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण किए जाने हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	शिमोगा- राणिबेन्नुर नई लाइन (96 किलोमीटर)	559	226	333
2	बेलगाम - धारवाड नई लाइन (73 किलोमीटर)	581	0	581
3	शिमोगा - हरिहर नई लाइन (79 किलोमीटर)	488	0	488
4	व्हाइटफील्ड-कोलार नई लाइन (53 किलोमीटर)	337	0	337
5	हासन-बेलूर नई लाइन (32 किलोमीटर)	206	0	206

कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण की स्थिति का सारांश इस प्रकार है:-

कर्नाटक में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	9,020 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	5,679 हेक्टेयर (63%)
अधिग्रहण हेतु शेष भूमि	3,341 हेक्टेयर (37%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, बहरहाल इनकी सफलता कर्नाटक राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात अनुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई आरंभिक और अंतिम स्थान तक संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालन संबंधी आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंजूरी
- अतिलंबी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरियाँ
- क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक स्थिति
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने वाले महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

\*\*\*\*\*